

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27 (11) ग्रावि/अनु-5/क्यू.सी./तृतीय पक्ष निरी. 2015-16 जयपुर, दिनांक 30/11/15

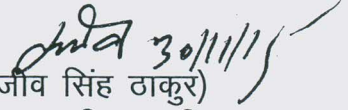
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद्,
राजस्थान समस्त (सीकर व झुन्डुनू को छोड़कर)

विषय:- मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास, व इंदिरा आवास योजनान्तर्गत अपूर्ण/बंद पडे आवासों के तृतीय पक्ष द्वारा भौतिक सत्यापन हेतु सूची प्रस्तुत करने बाबत।

प्रसंग:- विभागीय पत्र क्रमांक एफ 27 (11) ग्रावि/अनु-5/क्यू.सी./तृतीय पक्ष निरी. 2015-16 जयपुर, दिनांक 5 नवम्बर, 2015

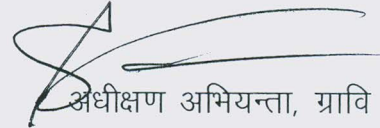
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सम्पादित/निर्माणाधीन कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं आवासों के भौतिक सत्यापन हेतु सरकारी/गैर-सरकारी कॉलेज/स्वयं सेवी संस्था/व्यक्तियों को प्रासांगिक पत्र द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। उक्त प्रासांगिक पत्र में वर्णित दिशा-निर्देशानुसार सूचीबद्ध तृतीय पक्ष संस्थाओं से अपूर्ण/बंद/ विवादित आवासों के भौतिक सत्यापन/ जांच हेतु कार्य आवंटित किया जाना है।

अतः योजनान्तर्गत विभिन्न वर्षों में स्वीकृत आवासों में अपूर्ण/बंद/विवादित/अन्य कारणों से पूर्ण नहीं हो पा रहे आवासों की ग्राम पंचायत/ पंचायत समितिवार लाभार्थियों की वर्षवार, योजनावार सूची एक्सल फोरमेट में सॉफ्टकॉपी तैयार कराकर दिनांक 4.12.2015 तक विभागीय ई-मेल pdengg_rdd@yahoo.com पर आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करावें।


(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रभारी अधिकारी, आवास, जिला परिषद्, समस्त को पालनार्थ।


अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि